Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com
ISSN:2584-105X Pg. 195 - 197

संसाधन की सिमितता और निर्धनता का समाजशास्त्रीय अध्ययन - शहर झुग्गी बस्तियों के सन्दर्भ में

डॉ. अलका श्रीवास्तव
सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र, मुमताज़ डिग्री कॉलेज, लखनऊ

Received: 18/06/2025
Accepted: 19/06/2025
Published: 20/06/2025
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.15757736

सारांश

यह शोध भारत में तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न सामाजिक विषमता और शहरी झुग्गी बस्तियों में व्याप्त निर्धनता का अध्ययन करता है। लखनऊ और कानपुर जैसे महानगरों में झुग्गी बस्तियों की समस्याओं, जैसे संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव पर केंद्रित, यह अध्ययन निर्धनता के सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण करता है और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए, 100 परिवारों पर प्राथमिक सर्वेक्षण तथा सरकारी रिपोर्ट्स का सहारा लिया गया है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि अध्ययनित झुग्गी बस्तियों में 70% परिवारों को स्वच्छ जल, 40% बच्चों को नियमित शिक्षा, और केवल 25% लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, जो देश भर की झुग्गी बस्तियों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। यह पत्र मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने जैसे नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है। अंततः, यह निष्कर्ष निकलता है कि संसाधनों का असमान वितरण एक गंभीर सामाजिक और नागरिक अधिकार का मुद्दा है जिसके समाधान के लिए शासन, समाज और शैक्षणिक समुदाय के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

***मुख्य शब्द**: शहरीकरण, सामाजिक विषमता, झुग्गी बस्तियाँ, निर्धनता, लखनऊ, कानपुर, संसाधनों की कमी, सरकारी योजनाएँ, प्राथमिक सर्वेक्षण, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, नीतिगत सुझाव, डिजिटल साक्षरता, रोजगार प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार*

प्रस्तावना

औद्योगिक क्रांति और आजादी के पश्चात भारत में शहरीकरण अत्यंत तीव्र गति से हुआ है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की खाई अधिक गहरी गई है। इस समस्या की गंभीर स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि इन शहरी संरचनाओं के भीतर झुग्गी बस्तियाँ उस हाशिए की पहचान हो गई हैं जहाँ संसाधनों की भीषण कमी और निर्धनता का प्रभाव देखा जा सकता है। निर्धनता एक सामाजिक आर्थिक समस्या है – आर्थिक इसलिये क्योंकि आर्थिक अभाव ही गरीबी को जन्म देता है, और सामाजिक इसलिए कि इससे उत्पन्न दशाएँ सामाजिक जीवन पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ए. पी. बर्नवास के शब्दों में, *"निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं है, यह सामाजिक तथा आर्थिक वंचना भी है।"* अर्थात निर्धनता एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसने अन्य सामाजिक समस्याओं जैसे बाल अपराध, अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि को जन्म दिया है।

भारत में निर्धनता की वर्तमान स्थिति पर यदि प्रकाश डालें तो ज्ञात होता है कि चरम गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 431 मिलियन जो कि वर्ष 1990 में थी, से घटकर 129 मिलियन वर्ष 2024 में रह गई है। नीति आयोग ने अपनी पहल एमपीआई रिपोर्ट में कहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे निर्धन राज्य में शामिल हैं और निर्धनता ही भारत में शहर झुग्गी बस्तियों की जननी कही जा सकती है। यद्यपि इस समस्या का सामना भारत के विभिन्न महानगर द्वारा किया जा रहा है और लखनऊ, कानपुर जैसे महानगर में इस समस्या ने एक सामाजिक चुनौती का रूप ले लिया है।

अध्ययन की आवश्यकता

भारत के कई शहरों की भांति लखनऊ में भी कई स्थानों पर झुग्गी बस्तियों का जाल देखा जा सकता है। ये झुग्गी बस्तियाँ कुछ ऐसी हैं जो कि अवैध रूप से बसी हुई हैं जबकि कुछ को सरकार योजनाओं के माध्यम से बसाया गया है। इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, सुरक्षा आदि का सामना दिन प्रतिदिन के जीवन में करना उनकी मजबूरी हो जाती है। यद्यपि शासन द्वारा अवैध बस्तियों को हटाने के कार्यवाही भी की जाती है लेकिन अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संसाधन मौजूद न होने के कारण पुनः ये झुग्गी बस्तियाँ बस जाती हैं।

लखनऊ में इन झुग्गी बस्तियों की स्थिति एक जटिल समस्या है। इसके निराकरण के लिये समय-समय पर सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न प्रयास किये जाते हैं और वास्तव में इन प्रयासों की आवश्यकता भी है। यदि वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि लखनऊ शहर में लगभग 610 झुग्गी बस्तियाँ हैं, जिसमें लगभग 7.7 लाख लोग निवास करते हैं, जो कि शहर जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत है। इतना बड़ा जनसंख्या बेहद सीमित संसाधन में अपना जीवन यापन कर रही है, जिससे मुख्यतः निम्न समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है:

1. रोजगार व आय के न्यूनतम स्तर
2. अपर्याप्त व असुरक्षित आवास व नौकरियाँ
3. पर्यावरण का अव्यवस्थित व हिंसात्मक होना
4. बहुत कम या न के बराबर सामाजिक सुरक्षा
5. अत्यधिक सीमित स्वास्थ्य या शिक्षा के अवसर

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य निम्न है:

1. संसाधन की स्थिति का अध्ययन शहर झुग्गी बस्तियों के सन्दर्भ में।
2. निर्धनता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण।
3. इन झुग्गी बस्तियों में सरकार योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
4. अन्ततः नीति निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान प्रश्न

इस शोध विषय के लिये कुछ झुग्गी बस्तियों में जाकर पूछे गए तथा कुछ विवरण सरकार रिपोर्ट्स आदि से भी संहित किए गए हैं। कुछ मुख्य प्रश्न निम्न हैं जैसे:

1. कौन सी मूल सुविधाओं की सबसे ज्यादा कमी है?
2. इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवार पर उनके निर्धनता का उनके जीवन शैली एवं उनके सामाजिक सम्बन्धों पर कैसा प्रभाव पड़ता है?
3. सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का आकलन व मूल्यांकन।

शोध पद्धति

शोध पत्र के लिये शोध की पद्धति में वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों विधियों द्वारा डेटा का संकलन किया गया है। सरकार रिपोर्ट्स, जनगणना, संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट इत्यादि का भी डेटा संकलन के लिये सहारा लिया गया है। इस शोध विषय में लखनऊ और कानपुर की झुग्गी बस्तियों में से 100 परिवार का अध्ययन चयन कर स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

शोध निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा जब इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों से संपर्क किया गया तो जो तथ्य सामने आए वे सरकार

सुविधाओं और योजनाओं की भी कलई खोलते हैं तथा साथ ही साथ इस तथ्य को भी स्पष्ट करते हैं कि भारत में यदि एक से दो शहर की झुग्गी बस्तियों में यह स्थिति स्पष्ट होती है कि 70% परिवार को स्वच्छ जल की नियमित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, 40% बच्चों की स्कूल की उपस्थिति नियमित दिखाई दे रही है और केवल 25% लोगों को ही प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है, तो सम्पूर्ण भारत में विद्यमान झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति भी लगभग दयनीय ही होगी।

सुझाव

यदि झुग्गी बस्तियों को समाप्त करना है तो उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। अतः अनिवार्य है कि शहर बस्तियों में विशेष शहर विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। उनके लिये मूलभूत सुविधाओं जैसे जल, स्वास्थ्य, शौचालय, शिक्षा आदि की तत्काल व्यवस्था की जाए। रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम तीव्र गति से प्रारंभ किये जाएँ और इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनकी जानकारी भी प्राथमिक रूप से मुहैया कराई जाए। डिजिटल साक्षरता और जागरूकता अभियान जितना अधिक हो इन बस्तियों में चलाया जाए जिससे यहाँ पर रहने वाले लोग, निवासी उन अभियान कार्यक्रमों से भली भांति परिचित हो, और स्वयं उसका लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष

इस सम्पूर्ण शोध पत्र से यह तथ्य उजागर होता है कि विशेषतः लखनऊ शहर में जहाँ 610 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 7.7 लाख नागरिक की यह स्थिति यह दर्शाती है कि संसाधन का असमान वितरण समाज के बड़े हिस्से को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखा हुआ है। यह स्थिति केवल आर्थिक संकट को ही उजागर नहीं करती बल्कि बहुत हद तक सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकार के लिये भी प्रश्न खड़ा करती है। और यदि हम इस स्थिति से निपटना है तो इसके लिये शासन, समाज और शैक्षणिक समुदाय तीनों को ही सामूहिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर आगे बढ़ना होगा।

संदर्भ सूची

1. ए. पी. बर्नवास का लेख – निर्धनता तथा उसके सामाजिक प्रभाव
2. Census of India, 2016 and Urban Update (2023)
3. UN-Habitat Reports 2023-24
4. NITI Aayog Urban Poverty Reports
5. Planning Commission of India
6. Sen, Amartya – *Development as Freedom*
7. Desai A.R. – *Social Background of Indian Nationalism*

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****